भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5323

जिसका उत्तर 5 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है।

15 चैत्र, 1945 (शक)

पीएमजी-दिशा की विशेषताएं

5323. डॉ. चन्द्र सेन जादौन:

श्री संजय जाधव:

श्री ओम पवन राजेनिबांलकर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उक्त अभियान के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले, महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नामित, प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अभियान के अंतर्गत विशेषकर परभणी और फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक प्राप्त उपलब्धियों क ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अभियान के अंतर्गत दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर धाराशिव (उस्मानाबाद), परभणी और फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिएसरकार देश भर के नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अनुरूप, ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को मंजूरी दी गई थी। पीएमजीदिशा योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- *यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात ग्राम पंचायत/गांव में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करने के लिए लागू की जा रही है।*
- *लाभार्थियों को 20 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें 5 मॉड्यूल शामिल हैं (i) डिजिटल उपकरणों का परिचय, (ii) डिजिटल उपकरणों का संचालन, (iii) इंटरनेट का परिचय, (iv) इंटरनेट का उपयोग कर संचार, (v) अनुप्रयोग इंटरनेट (नागरिक केंद्रित सेवाओं सहित) और डिजिटल कैशलेस लेनदेन करने के लिए वित्तीय साधनों का उपयोग।*
- *प्रशिक्षण सामग्री 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाती है। यह सामग्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, मोबाइल फोन के माध्यम से कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने पर सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) पर सामग्री, और पीओएस को भी शामिल किया गया है।*

- *उम्मीदवार के प्रशिक्षण के बाद, मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों नामत: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाईलिट), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) और आईसीटीएकेडमी ऑफ़ तमिलनाडु (आईसीटीएसीटीद्वारा आयोजित ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षित उम्मीदवारों का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाता है।)। सभी सफल उम्मीदवारों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं और सीधे उनके डिजी-लॉकर खातों में अपलोड किए जाते हैं।*
- *अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों के लिए, प्रशिक्षण केंद्र में एक फैकल्टी के साथ एक न्यूनतम भौतिक आईटी अवसंरचना निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण केंद्रों की जियो टैगिंग लागू कर दी गई है। प्रशिक्षण केन्द्र का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण प्रशिक्षण केन्द्र के अनुमोदन की प्रक्रिया का भाग है।*
- *राज्य और जिला स्तरों पर प्रभावी मूल्यांकन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाता है।*
- *प्रभावी प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए केंद्र/राज्य सरकार/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी/जिला प्रशासन तक डैशबोर्ड पहुंच प्रदान की गई है।*
- *शिकायत/शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।*

(ख): प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वित्तपोषित किया जाता है, इसलिए कोष स्वीकृत नहीं किया जाता है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है।

(ग) और **(ङ)**: महाराष्ट्र के धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले में लगभग 15,787 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 12,759 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 7,059 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। महाराष्ट्र के परबनी जिले में, लगभग 16,666 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 12,317 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 8,217 उम्मीदवारों को पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में, लगभग 33,200 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 29,744 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 24,092 उम्मीदवारों को उक्त योजना के तहत प्रमाणित किया गया है।

(घ): इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र घर से एक सदस्य को कवर करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। अब तक, पीएमजीदिशा योजना के तहत, लगभग 6.82 करोड़ उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 5.88 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4.37 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

(च) : सरकार ने उक्त अभियान के तहत धाराशिव (उस्मानाबाद), परभणी और फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों सहित दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें जागरूकता और प्रचार गतिविधियों को बढ़ाना शामिल है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और अभियान, कार्यशालाओं, सेमिनारों, डिजिटल वैन आदि के माध्यम से आबादी के विभिन्न क्षेत्रों को समावेशी तरीके से कवर करने के लिए इसका कई गुना विस्तार करना। देश भर में कवर न की गई ग्राम पंचायतों में नए प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने के प्रयास किए गए हैं। कम इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए दूर-दराज के स्थानों पर वाई-फाई-चौपाल स्थापित किए गए हैं। चिन्हित राज्यों के ग्रामीण आबादी वाले जिलों में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ग्रामीण स्कूलों को लगाया गया है।

******